



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 18, 2005/माघ 29, 1926

No. 22]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 18, 2005/MAGHA 29, 1926

भारतीय रिजर्व बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 18 फरवरी, 2005

संदर्भ सू.प्री.वि.(के का) सं. 2005/09.63.01/2004-05.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, एतद्वारा संलग्न भारतीय रिजर्व बैंक (भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षी बोर्ड) विनियमावली, 2005 को प्रकाशित करता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त है।

आर.डी. बर्मन, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/IV/38/2004/ असा.]

संलग्नक

भारतीय रिजर्व बैंक (भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षी बोर्ड) विनियमावली, 2005

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उपधारा (2) के उपबंध (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और ग्राहक.—(1) इन विनियमों को भारतीय रिजर्व बैंक (भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षी बोर्ड) विनियमावली, 2005 कहा जाए।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. विनियम सामान्य विनियमावली, 1949 के अस्तीकरण में नहीं।—इन विनियमों में यहां आगे किए गए स्पष्ट उपबन्ध को छोड़कर इन विनियमों के उपबन्ध भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 का अस्तीकरण न होकर उनके अतिरिक्त होंगे।

3. परिभाषा।—(1) इन विनियमों में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो :—

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) से है;

(ख) 'बैंक' से अभिप्राय अधिनियम द्वारा गठित भारतीय रिजर्व बैंक से है;

(ग) 'बैंकिंग कम्पनी' से अभिप्राय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5(ग) द्वारा यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी से है और उसमें बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 अथवा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित तत्सम नवा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 33) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित अनुषंगी बैंक और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित सहकारी बैंक शामिल होंगे;

(घ) 'केन्द्रीय बोर्ड' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल से है;

(ङ) 'बोर्ड' से अभिप्राय विनियम 4 के अन्तर्गत गठित भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम एवं पर्यवेक्षी बोर्ड के रूप में ज्ञात समिति से है;

(च) 'निदेशक' से अभिप्राय अधिनियम की धारा (8) की उपधारा (1) के उपबंध (ख) और (ग) के अन्तर्गत नामित केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक से है;

(छ) 'कार्यपालक समिति' से अभिप्राय विनियम 12 के अन्तर्गत गठित कार्यपालक समिति के रूप में ज्ञात उपसमिति से है;

(ज) 'सामान्य विनियमावली' से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 से है;

(झ) 'सदस्य' से अभिप्राय बोर्ड के सदस्य से है;

(ञ) 'अधिसूचित' से अभिप्राय शासकीय राजपत्र में अधिसूचित से है;

(ट) 'भुगतान और निपटान प्रणाली' से अभिप्राय उस प्रणाली से है जो दाता और हिताधिकारी के बीच होने वाले भुगतान को संभव बनाती है और जिसमें समाशोधन, निपटान या भुगतान सेवाएं या सभी शामिल हैं;

(ठ) 'उपाध्यक्ष' से अभिप्राय विनियम 4 के उप विनियम (2) के उपबंध (ख) के अंतर्गत गवर्नर द्वारा बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित उप गवर्नर से है;

(2) इसमें प्रयुक्त सभी अपरिभाषित अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित हैं, का तात्पर्य क्रमशः उन अधिनियमों में निहित अर्थ ही होगा।

4. बोर्ड की संरचना।—(1) एक समिति होगी, जिसे "भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम एवं पर्यवेक्षी बोर्ड" के रूप में जाना जाएगा (यहां आगे बोर्ड के रूप में उल्लिखित) :

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :—

(क) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, जो बोर्ड के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपगवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड के प्रभारी उप गवर्नर इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे;

(ग) गवर्नर द्वारा सदस्य के रूप में नामित भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के दो निदेशक।

(3) उप विनियम (2) के बावजूद कार्यपालक निदेशक प्रभारी भुगतान और निपटान प्रणाली, कार्यपालक निदेशक प्रभारी वित्तीय बाजार समिति (FMC) और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधान विधि परामर्शदाता बोर्ड की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

(4) बोर्ड, भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्थायी अथवा तदर्थ रूप से आमंत्रित कर सकता है।

5. बोर्ड के कार्य और अधिकार (शक्तियाँ)।—(1) बोर्ड बैंकिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग संस्थाओं का वह वर्ग जो अधिसूचित किया गया हो, के भुगतान और निपटान प्रणाली के विभिन्न तरीकों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले पर्यवेक्षण और विनियमन का तत्संबंधी कार्य और तत्संबंधी अधिकारों (शक्तियाँ) का प्रयोग करेगा।

(2) यह ऐसे उन कार्यों को भी करेगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हों।

(3) बोर्ड के कार्यों और अधिकारों में पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्यापकता को बिना किसी पूर्वाग्रह और विशिष्टता के अलावा निम्नलिखित मामले शामिल होंगे, यथा :—

(क) भुगतान और निपटान प्रणाली के साथ इलेक्ट्रॉनिक, गैर इलेक्ट्रॉनिक, घोलू और घोलू संबंधित हार्डवेयरों को प्रभावित करने वाले सीमापार की भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधित नीतियों का निर्धारण करना;

- (ख) वर्तमान और भविष्य की भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए मानक तैयार करना,
- (ग) भुगतान और निपटान प्रणाली को प्राधिकृत करना,
- (घ) भुगतान और निपटान प्रणाली की सदस्यता के लिए मानदण्ड निर्धारित करना जिसमें सदस्यता को बनाए रखना, रद्द करना और निरस्त करना शामिल है,

(ङ) उपरोक्त मामलों के लिए संविधि रूप से बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों और बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली के परिचालकों और उनके सदस्यों को समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रशासन का निरीक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी समझे जाने वाले कदम उठाना,

(च) भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जरूरी समझे जाने वाले कदम उठाना,

(छ) भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में लागू नियमों और विनियमनों में आवश्यक प्रशासनगत ढांचा तैयार करना।

(4) बोर्ड, इन विनियमनों के अंतर्गत अपने कार्यों और अधिकारों के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रीय भुगतान समिति से सलाह ले सकता है।

6. बोर्ड की सहायता।—रिजर्व बैंक के स्टाफ से गठित भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग द्वारा इस बोर्ड को सहायता प्रदान की जाएगी। यह विभाग सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और जहां आवश्यक होगा बोर्ड द्वारा बाहर से अथवा सीधी भर्ती या ठेके पर या सेवावृत्ति के आधार पर कार्यिक लिए जाएंगे।

7. नामन।—बोर्ड के लिए सभी नामन गवर्नर द्वारा केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से विनिर्दिष्ट अधिकृत के लिए किए जाएंगे।

8. पद रिक्ति।—जो सदस्य विनियम 11 के अंतर्गत बुलायी गयी बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहेगा, वह पद पर नहीं रहेगा।

9. बोर्ड की ओर से अधिकारों का प्रयोग कौन कर सकता।—सामान्य विनियमावली के विनियम 17 के उप विनियम (1) में किसी अन्य बात के होते हुए, किन्तु अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, रिजर्व बैंक द्वारा या उसकी ओर से किए गए स्वयं के संबंध में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सामान्य रूप में या रिजर्व बैंक के कारोबार के संचालन में विशेष रूप से दिए गए दिशा-निर्देश के होते हुए भी;

(1) बोर्ड को भुगतान और निपटान प्रणाली के संबंध में आवश्यक होने पर पर्यवेक्षण और विनियमन के अधिकार का प्रयोग करने का तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करने और कार्य करने का प्राधिकार होगा, जिन्हें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

(2) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, संयुक्त या अलग-अलग रूप से करेंगे।

(3) बैंक का कोई भी अन्य अधिकारी, यदि केन्द्रीय बोर्ड के पूर्वानुमोदन से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और जिस सीमा तक प्राधिकृत किया जाता है उस सीमा तक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के मामलों से संबंधित अधिकारों का प्रयोग करेगा।

10. साधारण विनियमावली की उपयुक्तता।—साधारण विनियमावली आवश्यक परिवर्तन सहित निम्नलिखित व्यवस्था नीचे दर्शाये गए अनुसार लागू होंगी :—

(क) सामान्य विनियमावली के विनियम 3, 4, 7, 13 और 24 बोर्ड के सदस्यों पर लागू होंगे,

(ख) विनियमावली 4 के उप विनियम 3 और 24 विनियम (4) के उप-विनियम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट बोर्ड की बैठक के आमंत्रितों और उप-समितियों के सदस्यों पर लागू होंगे,

(ग) विनियम 16, 18 और 19 भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के अधिकारियों पर लागू होंगे।

11. बोर्ड की बैठक और गणपूर्ति (कोरम)।—(1) बोर्ड के चालू कार्यों के निपटान के लिए बैंक कार्यालय में या उस क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर, जहां उस समय गर्वनर या उपाध्यक्ष का मुख्यालय स्थित हो, सामान्यतः तीन महीने में कम-से-कम एक बार बोर्ड की बैठक होगी।

(2) सदस्यों को भाग लेने हेतु पर्याप्त समय रहते नोटिस दी जाएगी।

(3) बोर्ड के कार्यों के संचालन के लिए गणपूर्ति (कोरम) हेतु दो सदस्यों जिनमें से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और दूसरा विनियम 4 के उप-विनियम (2) के उपबंध (ग) के अंतर्गत नामित सदस्य होंगे, की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(4) इन विनियमों में अन्यथा किए गए उपबंधों को छोड़कर अधिनियम और सामान्य विनियमावली के उपबंध बोर्ड की बैठकों पर वैसे ही लागू होंगे, मानो वे केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें हों।

12. उप-समिति का गठन.—बोर्ड अपने कार्यों में सहायता के लिए समय-समय पर यथावश्यक उप-समितियों का गठन करेगा जो कार्यपालक समिति के रूप में जाना जाएगा।

13. केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट.—बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

फाइल नं. :

नाम :

पदनाम :

RESERVE BANK OF INDIA

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th February, 2005

DIT(CO), 2005/09.63.01/2004-05.—In pursuance of Sub-section (1) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India hereby publishes the annexed Reserve Bank of India (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2005 which have received the sanction of the Central Government under Sub-section (1) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

R.B. BARMAN, Executive Director

[ADVT. III/IV/38/2004/Exty]

Annexure

RESERVE BANK OF INDIA (BOARD FOR REGULATION AND SUPERVISION OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS) REGULATIONS, 2005

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Sub-section (2) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Reserve Bank of India (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulations not in derogation of General Regulations, 1949.—Save as otherwise provided in these regulations, the provisions of these regulations shall be in addition to and not in derogation of the Reserve Bank of India General Regulations, 1949.

3. Definitions.—(1) In these regulations, unless, the context otherwise requires:—

(a) 'Act' means the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(b) 'the Bank' means the Reserve Bank of India constituted by the Act;

(c) 'banking company' means a banking company as defined in clause (c) of Section 5, read with clause (c c i) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and shall include a corresponding new bank constituted under Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or under Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (33 of 1955), a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), and a co-operative bank as defined in the Banking Regulation Act, 1949;

(d) 'Central Board' means the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India constituted under Section 8 of the Act;

(e) 'Board' means the committee known as the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems constituted under regulation 4;

(f) 'Director' means the Director of the Central Board nominated under clauses (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 8;

(g) 'Executive Committee' means a sub-committee known as the Executive Committee constituted under regulation 12;

- (h) 'General Regulations' means the Reserve Bank of India General Regulations, 1949;
- (i) 'Member' means a member of the Board;
- (j) 'National Payments Council' means a Technical Advisory Committee constituted by the Reserve Bank of India;
- (k) 'Notified' means notified in the Official Gazette;
- (l) 'Payment and settlement systems' means a system that enables payment to be effected between a payer and a beneficiary, and includes clearing, settlement or payment service or all of them;
- (m) 'Vice-Chairman' means the Deputy Governor nominated by the Governor as Vice-Chairman of the Board under clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 4.
- (2) All other words and expressions, used herein and not defined, but defined in the Act and the Banking Regulation Act, 1949, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

4. Composition of Board.—(1) There shall be a Committee to be known as the "Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems" (hereinafter referred to as the Board).

- (2) The board shall consist of the following members, namely.—
 - (a) Governor, Reserve Bank of India, who shall be the Chairman of the Board,
 - (b) Deputy Governors, Reserve Bank of India, out of whom the Deputy Governor who is the in-charge of the Payment and Settlement Systems, shall be the Vice-Chairman of the Board,
 - (c) Two Directors from the Central Board of the Reserve Bank of India to be nominated by the Governor as members.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the Executive Director In-charge of Payment and Settlement Systems, the Executive Director in-charge of the Financial Markets Committee (FMC) and the Principal Legal Adviser in the Reserve Bank of India shall be permanent invitees to the meetings of the Board.
 - (4) Persons with experience in the fields of Payment and Settlement Systems may be invited by the Board to attend its meetings either as permanent or as *ad hoc* invitees.

(5) Functions and powers of the Board.—(1) The Board shall perform such functions and exercise such powers of supervision and regulation as are deemed necessary in relation to the different modes of the payment and settlement systems of the banking companies, financial institutions and such classes of non-banking institutions as may be notified.

- (2) It shall also perform such other functions and exercise such other powers as may be notified by the Central Board, from time to time.
- (3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the functions and powers of the Board shall include the following matters, namely.—
 - (a) the laying down of the policies relating to the regulation and supervision of the Payment and Settlement Systems including electronic, non-electronic, domestic and cross-border Payment and Settlement Systems affecting domestic transactions;
 - (b) the laying down of the standards for both existing and future Payment and Settlement Systems;
 - (c) the authorisation of the Payment and Settlement Systems;
 - (d) the determination of the criteria for membership of Payment and Settlement Systems including continuation, termination and rejection of membership;
 - (e) Overseeing the administration of rules and guidelines framed under any statute for the purposes of the above matters and the directions issued by the Bank from time to time to the operators of the Payment and Settlement Systems and their members and taking such action as may be deemed necessary for ensuring the compliance;
 - (f) taking such steps as are deemed necessary for the effective regulation and supervision of the Payment and Settlement Systems;
 - (g) creating necessary administrative structure within the existing rules and regulations for ensuring effective regulation and supervision of the payment and settlement systems.
- (4) The Board may, in the performance of its functions and the exercise of its powers under these regulations, obtain the advice of the National Payments Council.

6. Assistance to the Board.—The Board shall be assisted by the Department of Payment and Settlement Systems, constituted from the staff of the Bank which shall report directly to the Board and if necessary, personnel from outside either on deputation or on contract or tenure basis, may be appointed by the Bank on the recommendation of the Board.

7. Nominations.—All nominations to the Board shall be made by the Governor in consultation with the Central Board for such term as may be specified.

8. Vacation of Offices.—A Member shall cease to hold office if he absents himself without the leave of the Chairman from three consecutive meetings of the Board convened under regulation 11.

9. Powers on behalf of the Board by whom to be exercised.—Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) of regulation 17 of the General Regulations, but subject to the provisions of the Act, any regulation made by the Central Board in regard to expenditure to be incurred by or on behalf of the Bank and any direction which may be given by the Central Board generally or in particular with regard to the Conduct of the business of the Bank namely:—

- (1) the Board is authorised to exercise the powers of supervision and regulation as deemed necessary in relation to the payment and settlement systems and such other powers and functions as may be notified by the Central Board from time to time.
- (2) the Chairman, the Vice-Chairman and the Members shall jointly and severally exercise such powers as may be specified from time to time by the Central Board.
- (3) any other officer of the Bank, if authorised, and to the extent that he is so authorised by the Board with prior approval of the Central Board, exercise all the powers in relation to matters pertaining to the Department of Payment and Settlement Systems.

10. Applicability of the General Regulations.—The following provisions of the General Regulations shall apply, *mutatis mutandis*, as specified below, namely:—

- (a) regulations 3, 4, 7, 13 and 24 of the General Regulations shall apply to the Members of the Board.
- (b) regulations 3 and 24 shall apply to the invitees to the meetings of the Board referred to in sub-regulations (3) and (4) of regulation 4 and the Members of sub-committees.
- (c) regulations 16, 18 and 19 shall apply to the officers of the Department of Payment and Settlement Systems.

11. Meetings of the Board and Quorum.—(1) The Board shall ordinarily meet at least once in three months at the office of the Bank or any other place in the area in which the Governor or in his absence the Vice-Chairman has his headquarters for the time being, to attend to the current business of the Board.

- (2) Members shall be given sufficient notice to enable them to attend.
- (3) Two Members of whom one shall be the Chairman or the Vice-Chairman, and the other who shall be a member nominated under clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 4 shall form a quorum for holding the meeting of the Board.
- (4) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions of the Act and the General Regulations shall apply to meetings of the Board, as if they were meetings of the Central Board.

12. Constitution of Sub-Committees.—The Board may constitute sub-committees to be known as Executive Committees as may be deemed necessary to assist it in its work from time to time.

13. Report to the Central Board.—The Board shall submit a report to the Central Board on an annual basis.

File No.

Name :

Designation :